

संकल्प प्रभात

संपादक - अनिल बी. तिवारी

4 मतभेद हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं

अब नहीं होगा फर्जी वैक्सीनेशन! 8

संक्षिप्त खबरें

राम भक्तों की आस्था पर नहीं पड़ा जमीन खरीद विवाद का असर, दिल खोलकर दान कर रहे लोग

अयोध्या- उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राजनैतिक पार्टियों की ओर से राममंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों का असर रामभक्तों की आस्था पर नहीं दिखाई दे रहा है। राम भक्त मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दे रहे हैं। ट्रस्ट के व्यवस्थापक प्रकाश गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन के खुलने के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंचकर रामलला के दरबार में दर्शन-पूजन कर रहे हैं। रामलला के मंदिर में रखे दान पात्र में राम मंदिर निर्माण के लिए दान चढ़ा रहे हैं। महीने के ५ से १० तारीख के बीच में ट्रस्ट और बैंककमी एक माह के आए दान का हिसाब करते हैं। रामलला के दानपात्र में ही महीने के करीबन ४० लाख रुपये दान स्वरूप चढ़ते हैं।

तीसरी लहर से निपटने के लिए हजार डॉक्टरों को दी ट्रेनिंग

मुंबई- मुंबई में संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बीएमसी पूरी तरह से जुटी हुई है। डॉक्टरों की ट्रेनिंग से लेकर मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बीएमसी ने अब ताब ऑनलाइन ट्रेनिंग वेब पांच सत्र आयोजित किए हैं, जिनमें एक हजार से अधिक डॉक्टरों को तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसमें सुम इलाकों में प्रैक्टिस करनेवाले जनरल फिजिशियन से लेकर पीडियाट्रिक डॉक्टर तक शामिल हैं। बता दें कि विशेषज्ञों ने मुंबई में तीसरी लहर कभी भी आने की आशंका जताई है। इसी को देखते हुए बीएमसी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने से लेकर डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने में जुटी हुई है।



इसी हफ्ते होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार!



नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दो दिन कैबिनेट विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ लंबी बैठकें की हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ये बैठकें बेहद गोपनीय रहीं। रविवार वाली बैठक शाम को करीब पांच बजे शुरू हुई और देर रात ११ बजे चक चलती रही। इसी

तरह परसों भी शाम पांच बजे से लेकर रात १२ बजे तक बैठक चली थी। ये बैठकें बेहद बेहद गोपनीयता बरतते हुए की गईं। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों ने इंडिया टीवी को बताया कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले दिन में हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि इस हफ्ते मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार तय

है, ज्यादा संभावनाएं हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार ७ से ११ तारीख के बीच हो। इस मंत्रिमंडल को लेकर ही पीएम मोदी ने ये बैठकें की हैं। इसमें संगठन की भी राय भी ली गई। इस बैठक में सांसदों के प्रदर्शन भी अलग-अलग चर्चा हुई है। चुनावी राज्यों पर भी चर्चा हुई है। **Caste Equation** पर भी चर्चा हुई है। कई सारे ऐसे नाम हैं, जिनके

बारे में काफी पहले से कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, बिहार में जेडीयू, महाराष्ट्र, कर्नाटक को लेकर भी होम वर्क लगभग हो गया है। कल जेपी नड्डा भी दिल्ली पहुंचने के बाद एक और कि उनके दिल्ली पहुंचने के बाद एक और मीटिंग मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो।

सभी भारतीयों का डीएनए एक, इस्लाम खतरे में होने के भय चक्र में न फंसें मुसलमान -मोहन भागवत

गाजियाबाद- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और मुसलमानों को “डर के इस चक्र में” नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। वह राष्ट्रीय मुस्लिम मंच द्वारा यहां ‘हिन्दुस्तानी प्रथम, हिन्दुस्तान प्रथम’ विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों में इस आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता कि उनका पूजा करने का तरीका क्या है। आरएसएस प्रमुख ने लिंगिंग (पीटकर मार डालने) की घटनाओं में शामिल लोगों पर हमला बोलते हुए कहा, “वे हिन्दुत्व के खिलाफ हैं।” हालांकि, उन्होंने कहा कि लोगों के खिलाफ लिंगिंग के कुछ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, “भय के इस चक्र में न फंसें कि भारत में इस्लाम खतरे में है।” उन्होंने कहा कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने जोर देकर

कहा कि एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों का गौरव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान ‘संवाद’ है, न कि



‘विसंवाद’। भागवत ने कहा, “हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात भ्रामक है क्योंकि वे अलग नहीं, बल्कि एक हैं। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।”

उन्होंने कहा, “हम एक लोकतंत्र में हैं। यहां हिन्दुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। यहां केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है।”

(शेष पृष्ठ ७ पर)

BJP के १२ MLA एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के चेंबर में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ ‘दुर्व्यवहार’ करने के आरोप में भाजपा के १२ विधायकों को १ साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। विधायकों

नहीं दी जाएगी। संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम



को निलंबित करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब ने पेश किया था, जो ध्वनि मत से पारित हुआ। अनिल परब ने कहा कि ‘निलंबन की अवधि के दौरान सभी १२ विधायकों को मुंबई और नागपुर में विधानमंडल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति

सतपुते और बंटी भांगडिया को विधानसभा से निलंबित किया गया है। घटना के बाद पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव और भाजपा विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने-अपने पक्ष सामने रखे।

(शेष पृष्ठ ७ पर)



संपादकीय...

वैक्सीन की प्रभावशीलता

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम गेब्रेसेयस ने कहा है कि लगभग १०० देशों में अधिक संक्रामक डेल्टा स्वरूप की पहचान की गई है और इसे देखते हुए दुनिया कोविड-१९ महामारी के 'बहुत खतरनाक दौर' में है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेल्टा वैरिएंट विकसित और परिवर्तित हो रहा है और यह कई देशों में कोविड-१९ का प्रमुख वायरस बन रहा है। उन्होंने कहा, 'मैंने पहले ही दुनियाभर के नेताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि अगले साल इस समय तक, हर देश में ७० प्रतिशत लोगों का टीकाकरण कर लिया जाना चाहिए।'

देश में अभी कोविड वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर अभी और अधिक जागरूकता लाने की जरूरत है क्योंकि कि यहां ६० साल से अधिक उम्र के लोगों में वैक्सीन लेने की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है और लगभग ५२ फीसदी बुजुर्गों ने टीके की अभी पहली खुराक तक नहीं ली है, जबकि अमेरिका में टीकाकरण को लेकर एक अध्ययन में पाया गया है कि वहां अब जितनी भी मौतें हो रही हैं, उनमें करीब ९९ फीसदी वे ही लोग हैं, जिन्होंने कोविड-१९ की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। मई में १८,००० से अधिक अमेरिकियों ने इस वायरस के कारण अपनी जान गंवाई, मगर उनमें से करीब १५० लोग ही ऐसे थे, जिन्होंने टीके की दोनों खुराकें ले रखी थीं। गौर करने वाली एक अहम बात यह भी है कि जनवरी के मध्य में वहां रोजाना औसतन ३,४०० लोगों की जान जा रही थी। तब वहां टीकाकरण अभियान शुरू हुए एक महीना ही हुआ था। मगर आज वहां कोविड-१९ के कारण मरने वालों की दैनिक संख्या ३०० से नीचे आ गई है।



मान्य आयु वर्ग के ६३ प्रतिशत अमेरिकी एक खुराक और करीब ५३ फीसदी दोनों टीके लगवा चुके हैं। अमेरिका से आए ये ब्योरे से टीकाकरण की अहमियत स्थापित करते हैं। हालांकि, ये यह भी बताते हैं कि अमेरिकी समाज में भी टीकों को लेकर संशय या दुराग्रह पालने वालों की कमी नहीं थी।

बहरहाल, वैक्सीन की प्रभावशीलता से जुड़ी इन जानकारीयों का लाभ दुनिया भर की सरकारों को उठाना चाहिए और अपने टीकाकरण अभियान को गति देनी चाहिए। खासकर भारत के लिए यह काफी अहम है, क्योंकि न सिर्फ इसको तीसरी लहर की आशंकाओं को निर्मूल करना है, बल्कि असंख्य लोगों के भय, पूर्वाग्रह को दूर कर उन्हें टीकाकरण केंद्रों तक लाना भी है। देश की विशाल आबादी को देखते हुए यह काफी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन यह अनिवार्य है और अनिवार्यता का कोई विकल्प नहीं होता। भारत का टीकाकरण अभियान पहले ही विसंगतियों का शिकार रहा है। एक तरफ, इसके हिस्से में सर्वाधिक टीके लगाने वाले चंद देशों में शुमार होने की उपलब्धि है, तो वहीं टीके की कमी के कारण लोगों का टीकाकरण केंद्रों से मायूस लौटना भी चिंताजनक है।

एक ओर, सौ फीसदी टीकाकरण वाले गांव हैं, तो दूसरी ओर टीकों की बर्बादी भी है। टीकों की दर, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और केंद्र-राज्यों में समन्वय की कमी जैसी बातों को एक तरफ रख भी दें, तो अब भी इसमें निरंतरता की कमी है। किसी दिन कोई राज्य लाखों टीके लगाने के कीर्तिमान रच रहा है, तो अगले ही दिन वह संख्या हजारों में सिमट आ रही है। नही! यह इवेंट मैनेजमेंट का विषय नहीं है, लोगों की जिंदगी और देश के भविष्य का गंभीर मसला है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें इस अभियान को गति देते समय टीकों की आपूर्ति, निरंतरता और क्षेत्रफल का समान रूप से ख्याल रखें।

इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिस आयुवर्ग में अब तक करीब सौ फीसदी टीकाकरण हो जाना चाहिए था, उसके ५२ प्रतिशत लोगों को एक खुराक भी नहीं लगी है। अमेरिकी अध्ययन के नतीजे बता रहे हैं कि न सिर्फ सरकारों, बल्कि समस्त सामाजिक समूहों और सजग नागरिकों को अब यह मकसद बनाना पड़ेगा कि टीकाकरण अभियान जल्द से जल्द सफल हो।

हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए समर्पित युवा डॉ. अर्पण जैन 'अविचल'

सैंकड़ों वर्षों का इतिहास और उस ऐतिहासिक कालखण्ड में हिन्दी भाषा के महत्व का आँकलन किया जाए तो निःसंदेह भारत के सांस्कृतिक वैभव की स्थापना में हिन्दी भाषा का महनीय स्थान है। आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी राष्ट्रभाषा और संवाद की सर्वमान्य कड़ी के रूप में हिन्दी भाषा ही स्वीकार्य रही। लगभग दो सौ वर्षों के निरंतर संघर्ष के उपरांत भी शासकीय दस्तावेजों में कहीं राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है और आज के भागदौड़ भरे दौर में युवाओं का कुल यदि हिन्दी भाषा के स्वाभिमान की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहा है तो निःसंदेह यह भाषा के उज्ज्वल भविष्य का भी कारक होगा और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी मील का पथर साबित होगा।

इस तारतम्य में वर्ष २०१६ से माखनलाल चतुर्वेदी जी के मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक युवा लेखक और पत्रकार डॉ. अर्पण जैन ने हिन्दी भाषा के प्रचार और प्रसार के साथ-साथ विस्तार की ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हुए मातृभाषा की शुरुआत की।

भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना मुख्य रहा और इसी के साथ, हिन्दी का प्रसार भी सम्मिलित रहा। डॉ. अर्पण जैन मूलतः कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ-साथ स्थापित पत्रकार भी हैं, उन्होंने २ दशकीय पत्रकारिता की



यात्रा में सैंकड़ों शहरों में अपने पत्रकार साथियों एवं लेखकों को संगठित कर अनथक हिन्दी योद्धा के रूप में कार्य किया। वे हिन्दीग्राम, साहित्यकारकोश, खबर हलचल न्यूज़, साहित्य ग्राम

डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' ने अब तक १० से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और मातृभाषा उन्नयन संस्थान के माध्यम से भारत के ११ लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हिन्दी में परिवर्तित करवाए, जिसके लिए उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स, लन्दन द्वारा ११ जनवरी २०२०, को विश्व पुस्तक मेला २०२०, प्रगति मैदान दिल्ली में विश्व कीर्तिमान प्रदान किया गया।

इसी के साथ, हिन्दी प्रचार के लिए सतत प्रयत्नशील हिन्दी योद्धा डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' को कई सम्मान व पुरस्कारों ने सम्मानित किया जा चुका है।

हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए संस्थान संघर्षरत है।

अपनी धुन के पक्के डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' का संकल्प है कि जब तक वे हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में स्थापित नहीं करवा देते, तब तक मिठाई नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसे संकल्पवान युवाओं की ज़िद के कारण ही भारत में क्रांतियाँ हुई हैं, हमने आज़ादी के स्वप्न को साकार होते देखा है।

आज भारत की जनता अपनी भाषा



पहले एक वेबसाइट से आरम्भ हुई यात्रा, जिसमें हिन्दी के लेखकों के लेखन को प्रकाशित करके प्रचारित करने का कार्य शुरू किया, फिर धीरे-धीरे युवाओं का दल सक्रिय हो गया और फिर आम जनता के हस्ताक्षर अन्य भाषाओं से हिन्दी में बदलवाने की कवायद शुरू हुई। इसी दौरान डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' ने मातृभाषा उन्नयन संस्थान की नींव रखी, जिसका उद्देश्य हिन्दी

पत्रिका सहित कई प्रकल्पों के माध्यम से हिन्दी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। भाषाई पत्रकारिता और लेखन से जुड़े होने से हिन्दी प्रेमी डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' भारतभर में मातृभाषा उन्नयन संस्थान की इकाइयों का गठन करके आंदोलन संचालित कर रहे हैं, और वे मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिन्दी ग्राम के संस्थापक भी हैं।

में न्याय पाने से वंचित है। भारत की कोई एक संपर्क भाषा नहीं है, जबकि हिन्दी भाषा भारत के पचास प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा बोली, समझी और लिखी जाती है। इसीलिए हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान करना सरकारों के लिए भी गौरव की बात है और वैश्विक रूप से भारत के भाषाई सौंदर्य में अभिवृद्धि का कारण भी है।

कहते हैं युवा का उल्टा वायु होता है यानी युवाओं में वायु की तरह वेग ही उनके संकल्पों की सिद्धि का माध्यम बनता है। डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' जैसे साहसी युवाओं के साथ भारत की साहित्यिक सहित आम मेधा को भी आना चाहिए और भारत में अपनी बोली-अपनी भाषा का महत्व स्थापित करते हुए मेरी हिन्दी-मेरा अभिमान भी गढ़ना चाहिए।



फर्जी 'पहचान' पर टिकट की 'किटकट', वैक्सिनेट लोगों को मिल सकती है लोकल में अनुमति

मुंबई- पिछले कुछ दिनों से मुंबई लोकल में फर्जी पहचान-पत्र से टिकट लेने वालों की तादाद बढ़ गई थी। पश्चिम और मध्य रेलवे से मिलाकर यात्री संख्या ३५ लाख के करीब पहुंच गई थी। बिना अनुमति वाले लोगों की भीड़ बढ़ने के बाद राज्य सरकार और रेलवे ने सख्ती शुरू कर दी है। रेलवे से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब कामकाजी दिनों में रोजाना करीब २२ लाख लोग चल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वैक्सिनेट लोगों को जल्द ही अनुमति दी जा सकती है। रेलवे के अनुसार चेकिंग के दौरान करीब ६०३ लोग फॉर्मैसी, मेडिकल या चैरिटेबल हॉस्पिटल के आईडी दिखाते हैं। इन पर संदेह होता है। इनमें से ज्यादातर

की जांच करने के बाद उनके कार्ड जाली निकलते हैं। कुछ बुकिंग क्लर्क ने बताया कि जब टिकट खरीदते वक्त आईडी दिखाने वाले लोगों से क्रॉस



चेकिंग के दौरान जीएसटी नंबर या कंपनी का अड्रेस पूछते हैं, तो वे लोग सुन्न हो जाते हैं। टिकट निरीक्षकों से बात करने पर पता चलता है कि सुबह भीड़ के कारण ज्यादा लोगों को रोक नहीं पाते हैं, इसलिए कई बार ट्रेनों में

चेकिंग करनी पड़ रही है। इस दौरान कई लोग फेक आईडी के साथ पकड़े जा रहे हैं। रेलवे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में ३५०० लोगों पर फर्जी कार्ड रखने का मामला दर्ज किया गया। इस दौरान १.५ लाख लोगों पर बिना टिकट यात्रा करने का जुर्माना लगाया गया। पश्चिम रेलवे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार १ अप्रैल से २५ जून तक फर्जी पहचान-पत्रों के ७४० केस बनाए थे। बुकिंग क्लर्क का कहना है कि सुबह पीक ऑवर्स में न तो ज्यादा पहचान-पत्र देख सकते हैं और न ही ज्यादा सवाल-जवाब होते हैं। लेकिन दोपहर के समय जब किसी पहचान-पत्र पर शक होता है, तो सवाल-जवाब के दौरान कई बार बहस हो जाती है।

पूर्व गृहमंत्री शिंदे बोले- कांग्रेस में खत्म हुई डिबेट और बातचीत की परंपरा

मुंबई- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि संगठन की विचारधारा और कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने के वास्ते अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की उनकी पार्टी की लंबे समय से चली आ रही परंपरा खत्म हो गई है और यह जानना मुश्किल है कि 'अभी हम कहां खड़े हैं।' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा पार्टी की विचारधारा, कार्यक्रमों और नीतियों का प्रचार-प्रसार करने के वास्ते अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की रही है।

सुशील कुमार शिंदे ने कहा, "यह प्रक्रिया रुक गई है और मुझे इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। यह जानना मुश्किल है कि हम

अभी कहां खड़े हैं।" शिंदे २९ जून को पुणे जिले के इंदोपुर में वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी रत्नाकर महाजन के ७५वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी की विचारधारा को समझने के लिए महाजन की बहस, परिचर्चा और महाराष्ट्र कांग्रेस की पत्रिका 'शिंदेरी' में उनके लेख कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं।

शिंदे ने कहा, "हमारी नीतियां गलत हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए प्रशिक्षण शिविरों की आवश्यकता है। मैं पार्टी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों के दौरान पैड और कलम लेकर बैठता था। दुर्भाग्य से, ऐसे प्रशिक्षण शिविर अब दुर्लभ हो गए हैं।"

मुंबईकरों की पसंद नहीं बन पाई मोनो, शुरुआत से ही परेशानी

मुंबई- मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने २०१४ में धूमधाम से मुंबई में मोनो रेल की शुरुआत की थी। सेवा शुरू होने के करीब ६ साल बीत



जाने के बाद भी मोनो रेल मुंबईकरों का दिल जीतने में असफल रही है। उम्मीद से बेहद कम प्रतिसाद मिलने के कारण मोनो रेल एमएमआरडीए के लिए सफेद हाथी बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, मोनो की वजह

से प्राधिकरण को रोजाना लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। कोविड-१९ के कारण लगे प्रतिबंध ने मोनो की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के पहले मोनो से रोजाना १० से १२ हजार यात्री सफर करते थे, जो अब घटकर रोजाना ५ हजार के करीब रह गए हैं। प्राधिकरण पिछले कुछ साल से मोनो ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी करने का भी प्रयास कर रहा है। एमएमआरडीए सेवा में सुधार करने के लिए पिछले करीब ३ वर्ष से नए रिक खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए कई बार गोबर टेंडर भी जारी किया गया था। मोनो का अलग और विशेष डिजाइन होने के कारण विश्व की कुछ कंपनियां ही रिक की सप्लाई के लिए दिलचस्पी दिखा रही हैं।

बीजेपी की मांगों पर राज्यपाल का सरकार से जवाब तलब

मुंबई- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाविकास आघाडी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने विधानमंडल के मॉनसून अधिवेशन की कालावधि बढ़ाने, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जल्द कराने और ओबीसी आरक्षण का फैसला होने तक स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित किए जाने के संदर्भ में लिखा है। इन तीनों मुद्दों पर सरकार से कार्रवाई करने को कहा है। राज्यपाल ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि नेता विपक्ष देवेन्द्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने २३ जून को उनसे मिलकर ये मांगें रखीं। फडणवीस ने राज्यपाल के समक्ष यह भी आरोप लगाया था कि सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रही है। विधानसभा का अध्यक्ष पद खाली नहीं रखा जा

सकता। वहीं, सरकार विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन की कालावधि को कम कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। वहीं सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते वह



विधान मंडल अधिवेशन की अवधि को सीमित रखना चाहती है, जरूरी विधायी काम भी निपटाए जा सकें और संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सके।

राज्यपाल के पत्र के बाद

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति की सरगमी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस्तीफे के बाद से पद रिक्त है। विधानसभा का पिछला अधिवेशन उपाध्यक्ष नरहरी झीरवल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था।

बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सरकार में शामिल तीनों दलों के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की ओर से कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण, एनसीपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटील तथा शिवसेना की तरफ से स्वयं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने भाग लिया।

राजा ने जताई मुख्यमंत्री बनने की इच्छा! समझिये, संभाजी राजे के सामने क्या होंगी चुनौतियां?

मुंबई- किसी राज्य की राजनीति करने वाला हर नेता एक दिन अपने सिर पर मुख्यमंत्री का ताज देखना चाहता है। इस बात को कुछ नेता कहते भी हैं और कुछ सही समय का इंतजार करते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है। संभाजी राजे को अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काफी मेहनत और जोड़तोड़ और सभी समाज को साथ लेकर चलना होगा।

बीड दौरे पर संवाद यात्रा के दौरान छत्रपति संभाजी राजे ने एक युवक के सवाल के जवाब में कहा था कि मुझे अगर सवाल करना है तो पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। आपको नए- पुराने मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए लेकिन वहां आपको जवाब

नहीं मिलेगा। खैर संभाजी राजे की यह महत्वाकांक्षा हकीकत के धरातल पर कितनी सफल हो सकती है, यह समझने की कोशिश करते हैं। छत्रपति संभाजी राजे भले ही शिवाजी महाराज के वंशज के रूप में जाने जाते हैं।

महाराष्ट्र में फिलहाल आरक्षण को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ मराठा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है तो वहीं ओबीसी समाज सरकार को ललकार रहा है। मराठा

समाज को आरक्षण मिले, इसलिए संभाजी राजे संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान जब छत्रपति संभाजी राजे से एक युवक ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और उप



मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए। 'मुझे सवाल करना है तो पहले मुझे सीएम बनाओ'।

मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए संभाजी राजे राज्य भर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि इस मुद्दे पर समाज का भी समर्थन संभाजी राजे को मिल रहा है। महाराष्ट्र में मराठा समाज से अन्य नेता और संगठन भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं लेकिन जो इनका जनसमर्थन छत्रपति को मिल रहा है। वैसे किसी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के बहुसंख्यक समाज में से एक मराठा समुदाय भी है लेकिन क्या एक समुदाय के लोगों को साथ लेकर या उन्हें खुश करके मुख्यमंत्री

की गद्दी मिलना संभव है?

महाराष्ट्र में मराठा समाज के अलावा ओबीसी समाज भी आरक्षण की मांग को लेकर मैदान में है। इसके अलावा संभाजी राजे महाराष्ट्र में जहां कहीं भी दौरे पर जाते हैं वह सिर्फ मराठा समाज के ही लोग या नेता नहीं आते बल्कि ओबीसी समाज के नेता और लोग भी शामिल होते हैं। ऐसे में इन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ इसका यह मतलब भी नहीं है कि ओबीसी नेताओं का समर्थन राजे को हासिल है। संभाजी राजे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर होने के बाद ओबीसी नेताओं का क्या रूप रहेगा इस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र में बीते कई सालों से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी समाज और मराठा समाज के बीच में वाद- विवाद शुरू है।

‘संकल्प सिद्धि संस्थान’ के मुंबई कार्यालय का उद्घाटन संपन्न

सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत मुंबई की अग्रणीय संस्था ‘संकल्प सिद्धि संस्थान’ के मुंबई कार्यालय का आज उद्घाटन संस्था के प्रमुख सलाहकार एवं आमदार श्री प्रसाद लाड जी के करकमलों द्वारा गोरगाँव पश्चिम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था के मुंबई सचिव विजय वाघेला एवं मुंबई अध्यक्ष संजय मिश्रा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोरीना नियमों के अंतर्गत जरूरत मंद दिव्यांगों के लिए प्रसाद लाड जी के हाथों राशन वितरण करवाकर कार्यालय का उद्घाटन करवाया।



कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आमदार प्रसाद लाड जी ने संस्थान के पदाधिकारियों एवं संस्थान के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की तथा सदैव संस्था का मार्गदर्शन एवं सामाजिक कार्यों में सहयोग करने का वचन दिया।

संस्थान के संस्थापक अनिल तिवारी जी ने कहा कि हमें अधिक से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर सामाजिक कार्य हेतु प्रेरित करते रहना चाहिये ताकि वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा सकें। एक तरफ जहां देश में एक बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी नशाखोरी की बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं विजय वाघेला एवं

संजय मिश्रा जैसे युवाओं ने अपने सामाजिक कार्यों द्वारा समाज में एक

संस्थान के कार्यों को गति मिलेगी और अधिक से अधिक सेवा कार्य



अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया हैं। इस कार्यालय के खुलने से मुंबई में

किये जा सकेंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय

नगरसेवक श्री हर्ष पटेल जी, श्री समीर देसाई जी (शिवसेना), श्री समीर दिवान जी, श्री सचिन भिल्लारे जी, तुषार गांधी जी, हिरेन तिवारी जी, RPI मुंबई सलमान खान जी, प्रदीप सिंह जी, रजनीकांत सोनी जी, जयेश यगवे जी, राहुल गुप्ता जी, सूरज गुप्ता जी, यश ठक्कर जी, जगदीश वाघेला जी, विवेक शुक्ला जी, पवन शर्मा जी, विवेक शुक्ला जी, सम्मान बटे जी, संस्थान के उपाध्यक्ष नरेश मखीजा जी, शिवाकांत तिवारी जी, भावेश सिंह जी, सचिन कदम जी, अजय मिश्रा जी, अजित तिवारी जी प्रमुख रूप से उपस्थित रहें।

शिवसेना से फिर गठबंधन के सवाल पर फडणवीस- मतभेद हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं

महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उथल पुथल काफी तेज हो गई है। सरकार अभी महा विकास अघाड़ी की है, लेकिन चर्चा बीजेपी और शिवसेना की होने लगी है। कहा जा रहा है कि दो पुराने साथी फिर एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब ये अटकलें भी इसलिए जोर पकड़ रही हैं कि क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई बार बड़े नेताओं द्वारा इस तरह इशारा किया गया है।

अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस ओर इशारा कर दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी और शिवसेना फिर साथ आ सकते हैं, क्या फिर कोई गठबंधन की उम्मीद हो सकती है, इस सवाल पर देवेंद्र फडणवीस कह गए कि वे शिवसेना के दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने बोला कि राजनीति में किंतु-परंतु के लिए कोई जगह नहीं होती। हमारे शिवसेना से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी दुश्मन नहीं है। अब फडणवीस का ये

कहना ही दिखाता है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच जो विधानसभा चुनाव के बाद तकरार बढ़ गई थी, अब वो कम होती दिख रही है।

वैसे भी देवेंद्र फडणवीस से पहले शिवसेना



के कुछ नेता भी दबी जुबान में फिर बीजेपी से गठबंधन की बात कर चुके हैं। कुछ समय पहले सीएम उद्धव ठाकरे की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद

शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ कर दी थी और बीजेपी की सफलता का क्रेडिट भी उन्हें दे दिया। ऐसे में यूं तारीफ करने वाले बयान देना, सीएम की पीएम से मुलाकात होना और अब फडणवीस का ये कहना कि शिवसेना उनकी दुश्मन नहीं, कई तरह के राजनीतिक संदेश दे रहा है। अब इस तरह के तमाम बयान एक तरफ शिवसेना को फिर बीजेपी के करीब ला सकते हैं तो वहीं महा विकास अघाड़ी के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकते हैं। कुछ समय से एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी काफी सक्रिय हो गए हैं। उनकी भी लगातार दूसरे दल के नेताओं संग अहम बैठकें हो रही हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस भी फिर अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में अनिश्चितताओं का खेल जारी है जहां पर कब क्या हो जाए, ये बता पाना मुश्किल साबित हो रहा है।

नहीं रहे वरिष्ठ फिल्म प्रचारक बी के वर्मा

मुंबई (काली दास पाण्डेय)- बॉलीवुड के चर्चित वरिष्ठ फिल्म प्रचारक बी के वर्मा का निधन बीते मंगलवार को हो गया। ८० वर्षीय बी के वर्मा ने बतौर स्टिल फोटोग्राफर अपना फिल्मी कैरियर ६० के दशक में शुरू किया था। बाद में फिल्म पत्रकार/प्रचारक और कार्यकारी फिल्म निर्माता के रूप में फिल्म जगत में अपनी विशिष्ट छवि कायम करने में कामयाब रहे। २०१९ के अक्टूबर माह में बी के वर्मा गंभीर रूप से बीमार पड़े और तब से बीते मंगलवार की रात तक जुहू स्थित आवासीय फ्लैट 'गुलशन' से नानावटी हॉस्पिटल का सफर तय करते हुए ज़िन्दगी और मौत से एक साथ जंग लड़ते रहे। देव आनंद, दारा सिंह और संजय खान की फिल्मों के पसंदीदा पीआरओ के रूप में वो जाने जाते थे। उनके पीआरशिप में निर्मित फिल्मों में 'नानक दुखिया सब संसार' १९७०, 'मेरा देश मेरा धर्म' १९७३, 'भगत धन्ना जाट' १९७४, 'सवा लाख से एक लड़ाऊ' १९७६, 'चांदी सोना' १९७७, 'ध्यान भगत' १९७८, 'भक्ति में शक्ति' १९७८, 'अब्दुल्ला' १९८०, 'रुस्तम' १९८२, 'काला धंधा गोर लोग' १९८६, और 'करण' १९८९४ के नाम उल्लेखनीय हैं। बतौर पीआरओ उन्हें झारखंड की धरती से जुड़ी फिल्म 'अग्रिकुंड' परिवर्तित टाइटल-अग्रिमार्ग के लिए निर्माता निर्देशक रवि कौशल ने अनुबंधित किया था।



प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण श्री हरिहर शिव मंदिर परिसर

मुंबई से सटे पालघर जिले में वाडा तालुका के घोड़माल नामक गांव में वैतरणा नदी के तट पर स्थित यह शिवालय प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है।

आध्यात्मिक दृष्टि से इस स्थान का वातावरण ध्यान योग करने हेतु अत्यंत उपयुक्त है शिवालय से निकलते मंत्रों की ध्वनि स्वतः ही साधना हेतु आपको प्रेरित एवं

आकर्षित करने लगती हैं। इससे ध्यान साधना की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। यहां शिवालय के साथ ही एक दिव्य गौशाला भी है। जहाँ करीबन ७५ से अधिक बेसहारा

गौवंशों की देखरेख की जाती है।

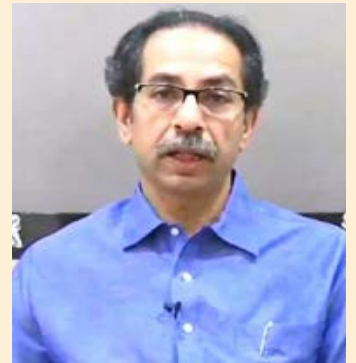
गौवंशों के विचरण हेतु वृंदावन सा प्रतीत होता आम, अमरूद एवं चीकू के बड़े बड़े बगीचों का समूह स्थापित किया गया है। यहां गौ माता को विचरण करते देखने मात्र से सुखद अनुभूति होती है। साथ ही आपको यहां गौसेवा का भी अवसर

भी प्रदान किया जाता है जिससे आप पूज्य के भागी बनते हैं। इन बगीचों में विश्व के विभिन्न प्रकार के आम एवं अमरूद के पौधों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। इन बगीचों में टहलने मात्र से आपको मानसिक शांति की प्राप्त होगी।



महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने प्रचार-पब्लिसिटी में खर्च कर दिए १५५ करोड़!

महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार ने सिर्फ प्रचार और पब्लिसिटी पर अब तक १५५ करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। ये चौकाने वाला खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है जहां पर एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने उच्च और पब्लिक रिलेशन से इसकी जानकारी मांगी थी। बताया गया है कि पिछले १६ महीनों में सरकार ने सिर्फ प्रचार के लिए १५५ करोड़ खर्च किए हैं। इसमें भी सोशल मीडिया के जरिए प्रचार पर ज्यादा खर्च किया गया है।



अनिल गलगली की तरफ से ये जानकारी मांगी गई थी। जानने का प्रयास रहा था कि जब से महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी की सरकार बनी है, प्रचार पर कितना खर्च किया गया है। अब सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय की तरफ से ११ दिसंबर २०१९ से १२ मार्च २०२१ तक के आंकड़े उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बताया गया है कि साल २०१९ में राज्य सरकार की तरफ से प्रचार पर २०.३१ करोड़ खर्च किए थे। वहीं इसमें भी १९.९२ करोड़ तो टीकाकरण के प्रचार पर खर्च किए गए थे। वहीं फिर साल २०२१ में राज्य सरकार की तरफ से १०४.५५ करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसमें ५.९६ करोड़ महिला दिवस के मौके पर खर्च

हुए, ९.९९ करोड़ पदम डिपार्टमेंट पर, १९.९२ करोड़ एन के प्रचार पर और विशेष प्रचार अभियान पर २२.६५ करोड़ खर्च कर दिए गए। वहीं सोशल मीडिया को लेकर बताया गया है कि सरकार की तरफ से १.१५ करोड़ खर्च किए गए। दूसरे कई विभाग के प्रचार-प्रसार पर भी भारी-भरकम रकम खर्च की गई है।

अब २०२१ में भी सरकार की तरफ से सिर्फ १२ मार्च तक १२ विभागों पर २९.७९ करोड़ खर्च कर दिए गए हैं। इसमें भी सोशल मीडिया पर ४५ करोड़ खर्च किए गए हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से सोशल मीडिया पर २.४५ करोड़ रुपये की लागत से २० लाख रुपये खर्च करने का अनुमान है। जल जीवन मिशन पर भी सरकार ने १.८८ करोड़ खर्च किए हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से भी प्रचार पर काफी खर्च किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक इस विभाग ने ५० करोड़ में से ४८ करोड़ तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही खर्च किए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ३.१५ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली बताते हैं कि ये आंकड़ा १५५ करोड़ से सभी ज्यादा हो सकता है। उनके मुताबिक DGI के पास भी सारे आंकड़े नहीं रहते हैं, ऐसे में प्रचार पर और ज्यादा रुपये खर्च किए गए होंगे। वहीं उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि 'क्रिएटिव' के नाम पर कई और दूसरे खर्च भी किए गए हैं जिसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। उनकी तरफ से मांग हुई है कि विभागीय स्तर पर होने वाले तमाम खर्चों को राज्य सरकार अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।

पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा सियासी संग्राम, बांकुरा में आपस में भिड़े बीजेपी-टीएमसी कार्यकर्ता

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में हिंसक झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांकुरा में देर शाम दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। मारपीट में बीजेपी के ६ और टीएमसी के ४ कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल, सोनामुखी में बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। बीजेपी का आरोप है कि कार्यक्रम को बंद कराने के लिए टीएमसी के गुंडे वहां पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। बीजेपी का दावा है कि सोनामुखी से विधायक दिवारक घरामी पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हालांकि टीएमसी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष

के नेता शुभेंदु अधिकारी ने देर रात ट्वीट करके आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक दिवारक घरामी पर रविवार



को मानिक बाजार पंचायत क्षेत्र में टीएमसी के गुंडों द्वारा हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि हमले में सात भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए और उन्हें बांकुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर करना पड़ा है।

हालांकि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश विश्वास ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाजपा के बिष्णुपुर के आयोजन जिलाध्यक्ष सुजीत अगस्ती ने कहा कि घरामी पर शारीरिक हमला नहीं किया गया था। उन्होंने दावा किया कि रविवार शाम को मानिकबाजार पंचायत क्षेत्र में एक बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। सुजीत अगस्ती ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता जब सोनामुखी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने गए तो उनमें से दो को हिरासत में ले लिया गया। तृणमूल कांग्रेस के एक जिला नेता ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी 'झूठ' बोल रहे हैं, हमें इस तरह की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

बुल्ढाणा में राजनीतिक बवाल, शिवसेना MLA के बयान पर पैंथर सेना ने दी भीमा कोरेगांव दोहराने की धमकी

महाराष्ट्र के बुल्ढाणा का एक मामूली विवाद राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। बुल्ढाणा के खामगांव तहसील के चितोड़ा गांव में दो परिवारों के बीच आपसी झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद गांव में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पहुंचे और १० हजार लोगों के लाने की धमकी दी। इसके बाद ऑल इंडिया पैंथर सेना ने भीमा कोरेगांव दोहराने की धमकी दी।

दरअसल, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर कोई भी अत्याचार निवारण कानून का दुरुपयोग करता है और झूठी शिकायत दर्ज करवाता है तो दूसरे पक्ष को उस व्यक्ति के खिलाफ डकैती की शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि अत्याचार निवारण कानून सुरक्षा के लिए है न कि ब्लैकमेल एवं दुरुपयोग के लिए, अगर कोई अत्याचार की झूठी शिकायत करता है तो आपको उस व्यक्ति के खिलाफ उलटा डकैती की शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ये लोग अत्याचार की शिकायतें वापस ले लेंगे, कृषि भूमि को लेकर विवाद अत्याचार नहीं है। वायरल वीडियो में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ कहते

हैं कि समाज विरोधी तत्वों की कोई जाति या धर्म नहीं होता, ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए युवाओं की टीम बनाएं, डकैती का केस दर्ज कराएं, अगर थानेदार केस दर्ज नहीं करता है तो मैं १०,००० लोगों के साथ आऊंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा।



शिवसेना विधायक के बयान का विरोध करते हुए अखिल भारतीय पैंथर सेना के अध्यक्ष दीपक केदार ने कहा कि अगर शिवसेना विधायक १०,००० लोगों की भाषा बोल रहे हैं, तो वह १०,००० लोगों को शिवाजी पार्क में लाएं और मैं ५०० महारों को लाऊंगा और फिर से भीमा-कोरेगांव करके दिखाऊंगा।

यूपी में सियासी सरगर्मी के बीच अखिलेश यादव से मिले आप सांसद संजय सिंह

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने में शेष बचे हैं ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच आप के सांसद संजय सिंह सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे हैं। संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट ऑफिस में हो रही है। दोनों के बीच बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह अखिलेश को उनके जन्मदिन की बधाई देने वहां पहुंचे हैं। वहीं सियासी गलियारों में इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। आप के सांसद संजय सिंह

यूपी के प्रभारी हैं। संजय सिंह काफी सक्रिय हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। किसान आंदोलन से लेकर राम मंदिर के



मसले पर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर जमीन खरीद में हुए घोटाले में भाजपा के मेयर, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत नौ लोगों के खिलाफ अयोध्या की नगर कोतवाली तहरीर देकर सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने की सोमवार को मांग की थी। संजय सिंह ने कहा कि एक के बाद एक कई घोटालों को मैंने उजागर किया। भाजपा नेताओं और ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर किस तरह से दो करोड़ की जमीन

पांच मिनट में साढ़े १८ करोड़ रुपये में खरीद ली गई। भाजपा के मेयर, उनके नेता २० लाख की जमीन को ढाई करोड़ में ट्रस्ट को बेचते हैं, ये सभी घोटाले मैंने सबके सामने रखे हैं। इतना सब कुछ सामने लाने के बावजूद अब तक भाजपा की केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार ने कोई जांच नहीं कराई, न केंद्रीय एजेंसी से कोई जांच हुई और न पुलिस वालों से कोई जांच कराई गई। भाजपा नेता और ट्रस्ट के लोग घूम-घूम कर मुझ पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तैयार होगा काशी विश्वनाथ धाम, पीएम के ड्रीम प्रॉजेक्ट को साकार करने में जुटे १००० कामगार

वाराणसी- उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम के ड्रीम प्रॉजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य ने फिर रफ्तार पकड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद फिर से निर्माण क्षेत्र में कामगारों की संख्या



को बढ़ाया गया है। १ हजार से अधिक मजदूर वाराणसी में पीएम के सपने को साकार करने में जुटे हैं। यूपी की योगी सरकार भी २०२२ विधानसभा चुनाव से पहले काशी विश्वनाथ धाम को तैयार कर चुनाव में काशी के विकास मॉडल को नजीर के तौर पर पेश करने में जुटी

है। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि १५ नवम्बर तक काशी विश्वनाथ धाम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अभी तक लगभग ६५ फीसदी तक काम पूरा भी हो गया है। बाकी तय समय में उम्मीद है कि काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ५५ हजार स्क्वायर मीटर में तैयार हो रहे काशी विश्वनाथ धाम में यात्री सुविधा केंद्र, दो म्यूजियम, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, अस्पताल, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, मंदिर चौक, जलपान केंद्र, गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है। प्रस्तावित २९ भवनों में से सभी भवनों के ढांचे को तैयार कर उसे गुलाबी पत्थरों से सजाने और संवारने का काम भी जारी है। ६०० करोड़ की लागत से तैयार काशी विश्वनाथ धाम में चुनार और बालेश्वर के गुलाबी पत्थरों के अलावा मकराना का मार्बल, कोटा स्टोन के अलावा तीन तरह के ग्रेनाइट लगाए जा रहे हैं।

UP में मछली पालन के नाम पर सैकड़ों किसानों को 'जाल' में फंसाया, फिर करोड़ों ठगे

आगरा- यूपी के आगरा में फिश फॉरच्यून प्रोड्यूस कंपनी ने सैकड़ों किसानों को चुना लगाकर करोड़ों की ठगी की है। एक किसान को जब इसकी जानकारी हुई तो उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। किसान ने कंपनी को फिश पालन उद्योग लगाने के लिए ५५ लाख रुपये दिए थे। किसान के पुत्र ने थाना ताजगंज में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया है। इस मामले में पुलिस ने कंपनी के एजेंट लाखन सिंह कुशवाहा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश जारी है।

गांव गंगरुआ थाना ताजगंज के रहने वाले राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले आगरा के लाखन सिंह कुशवाहा, शेतुसलज और आतिबु सिंह कंपनी के एजेंट बनकर उसके पास आए थे। उन्होंने आ

फर दिया था कि तुम तालाब खुदवाओ कंपनी तुम्हें मछली, दाना और महीनेदारी देगी। एजेंटों ने उससे कहा कि साढ़े पांच लाख लगाओ तो ११ लाख मिलेगा और ११ लाख लगाओ तो २२ लाख रुपये मिलेगा। इनकी बातों में आकर



उसने ५५ पांच लाख रुपये लगा दिए थे। शुरुआत में उसके पास कुछ पैसे कंपनी के द्वारा आए, लेकिन इसके बाद पैसे आने बंद हो गए। ये रुपये उसके पिता ओमप्रकाश ने अपनी जमीन बेचकर लगाए थे। राजकुमार ने बताया कंपनी के सीईओ विजेंद्र कश्यप और विनय शर्मा ने मछली पालन के लिए उन्हें

७५ हजार महीने देने की बात कही गई। कुछ समय तो उसके पास रुपये आए, लेकिन बाद में बंद हो गए तो उसने कंपनी से संपर्क किया मगर कंपनी के अधिकारी टालमटोल करते रहे। उसने बताया कि उसके साथ उसके रिश्तेदारों और आसपास के मिलने वाले किसानों ने भी रुपये लगाए थे। ऐसे सैकड़ों किसान आगरा और उसके आसपास के बताए जा रहे हैं। राजकुमार ने यह भी बताया कि कंपनी के लोग फोन पर लगातार धमकियां देते हैं। कुछ लोग उनके घर पर आए थे जो उन्हें केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। राजकुमार ने बताया कि फिश फॉरच्यून कंपनी गुरुग्राम हरियाणा की है। कंपनी के सीईओ विजेंद्र कश्यप निवासी गुरुग्राम, विनय शर्मा ने आगरा के करीब ४०० से ५०० लोगों को मछली पालन का उद्योग लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की है।

पृष्ठ १ से जारी....

BJP के १२ MLA एक...

भास्कर जाधव ने कहा कि 'महाराष्ट्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे सामने का माइक तोड़ दिया। बीजेपी के विधायकों ने मुझे मां-बहन की गालीयां दीं। इन्हें रोकने की कोशिश की तो जैसे गुंडे होते हैं, वैसे बीजेपी के विधायकों ने व्यवहार किया।' उन्होंने कहा कि 'विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है कि मैंने उनको गाली दी।'

देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। फडणवीस ने कहा, "यह एक झूठा आरोप है और विपक्षी सदस्यों की संख्या को कम करने का प्रयास है। ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि हमने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे पर सरकार के झूठ को उजागर

किया है।"

उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी को गाली नहीं दी। नेता प्रतिपक्ष फडणवीस ने कहा, "शिवसेना विधायकों ने ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मैं अपने विधायकों को अध्यक्ष के कक्ष से बाहर ले आया था।" पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया कि शेलार के माफी मांगने पर मामला समाप्त हो गया। जाधव ने जो कहा वह "एकतरफा" पक्ष था।

इससे पहले, राकांपा नेता और मंत्री नवाब मलिक ने भाजपा सदस्यों पर भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा की कार्यवाही को चार बार स्थगित किया गया।

सभी भारतीयों का...

भागवत ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि वह न तो कोई छवि बनाने के लिए कार्यक्रम

में शामिल हुए हैं और न ही वोट बैंक की राजनीति के लिए। उन्होंने कहा कि संघ न तो राजनीति में है और न ही यह कोई छवि बनाए रखने की चिंता करता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, "यह (संघ) राष्ट्र को सशक्त बनाने और समाज में सभी लोगों के कल्याण के लिए अपना कार्य जारी रखता है।"

गाजियाबाद में 'दि मीटिंग्स ऑफ माइंड्स' बुक लॉन्च पर आए प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वोट की राजनीति में हम नहीं पड़ते। राष्ट्र में क्या होना चाहिए, इस बारे में हमारे कुछ विचार हैं। अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम चुनाव में भी लगाते हैं। हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं।

पुस्तक विमोचन करने से पहले मोहन भागवत ने आरएसएस और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दो दिन रहेंगे।

मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत के बाद चार नाबालिगों का विवाह रुका

नोएडा- गौतमबुद्ध नगर जिले के नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक ही स्कूल के चार नाबालिग छात्र-छात्राओं का विवाह चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस ने मिलकर रुकवा दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत आधार पर की गई है। ग्रेटर नोएडा चाइल्ड हेल्पलाइन के अदनान उस्मानी ने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल के जरिए शिकायत की थी कि कोतवाली नॉलेज पार्क क्षेत्र के एक गांव में दो नाबालिग बहनों का विवाह पड़ोस के गांव के दो नाबालिग भाइयों से किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने

चाइल्ड लाइन टीम को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की तो पता चला कि गांव में विवाह की तैयारी चल रही है। यह विवाह शुक्रवार को होना था। टीम ने चारों नाबालिग छात्र-छात्राओं से बात की और उनकी उम्र से संबंधित दस्तावेजों की गहनता से जांच-पड़ताल की।

उन्होंने बताया कि इस दौरान टीम को जानकारी मिली कि जिन लड़कियों का विवाह होने वाला है उनकी आयु १४ से १६ वर्ष के बीच है। साथ ही जिन लड़कों से विवाह संपन्न होने है वे दोनों लड़के भी नाबालिग हैं। इसके बाद हरकत में आई टीम ने विवाह रुकवा दिया।



ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा- 'असदुद्दीन ओवैसी भी बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री'

बलिया: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश के मतदाता बन जाएं तो वह भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। भाजपा की पूर्व सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजभर ने शुक्रवार को कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मतदाता बन जाएं, तो वह भी

यहां के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश में मुसलमान करीब



२० फीसदी हैं। उनकी हिस्सेदारी है तो सत्ता में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनका अधिकार है, मुसलमानों का भी हिस्सा है।' उन्होंने

सवाल किया, 'मुसलमान का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या मुसलमान होना गुनाह है?' उन्होंने कहा कि अलगाववाद व पाकिस्तान की बात हमेशा करने वाली महबूबा मुफ्ती से समझौता कर भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाई। राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि वह चालाक निकले और उत्तराखंड से आकर उत्तर प्रदेश के मतदाता और फिर मुख्यमंत्री बन गए।

इन्हें जुलाई के आखिर तक मुंबई लोकल ट्रेनों में नहीं मिलेगी सफर की इजाजत, हाईकोर्ट ने भी किया इनकार

कोरोना महामारी के चलते मुंबई लोकल ट्रेनों में केवल कुछ ही लोगों को सफर की इजाजत है। हालांकि मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर को लेकर कई संगठनों ने



खासतौर से मुख्यमंत्री से अनुरोध कर इजाजत मांगी है। दरअसल कोविड-१९ की वजह से सार्वजनिक वाहनों में यात्रा पर लगी पाबंदियों के बीच वकीलों को मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति मांगी थी जिसको लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से

पूछा था। हालांकि अब बंबई उच्च न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया है। बॉम्बे ण का कहना है कि वह वकीलों को कम से कम जुलाई के अंत तक उपनगरीय ट्रेनों

से यात्रा करने की अनुमति नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा, 'हम वकीलों को कम से कम जुलाई के अंत तक मुंबई लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र राज्य ण्ड-१९ टास्क फोर्स ने महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताई

है।' इससे पहले मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने राज्य सरकार से वकीलों को यात्रा की अनुमति के संबंध में सवाल महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए किया था।

फ्लैट खरीदारों से ठगी के मामले में मुंबई की कंपनी के प्रवर्तक को ईडी ने गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि फ्लैट खरीदारों से करीब ५० करोड़ रुपये की ठगी करने की आरोपी मुंबई की कंपनी के निदेशक को धन शोधन के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने बताया कि मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप के निदेशक गोपाल अमरलाल ठाकुर को बृहस्पतिवार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को आठ जुलाई तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा "फ्लैट खरीददारों से पैसे लेकर और काफी समय बीतने के बाद भी उनके नाम फ्लैट पंजीकृत नहीं करने व धोखाधड़ी करने के आरोप" में दर्ज कई प्राथमिकियों और आरोप पत्रों का अध्ययन करने के बाद धनशोधन का मामला दर्ज किया।

मुंबई के अंधेरी स्टेशन का बदलेगा चेहरा, बीओटी की तर्ज पर बनेगा इंटीग्रेटेड स्टेशन

मुंबई- दुनिया की सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्टेशनों में शामिल मुंबई के अंधेरी स्टेशन का चेहरा बदलने का फैसला भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ने लिया है। अंधेरी स्टेशन को बीओटी के तर्ज पर इंटीग्रेटेड स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए पुनर्विकास का कुल क्षेत्रफल ४.३१ एकड़ है। पहले चरण में २.१ एकड़ और बचे हुए क्षेत्रफल पर दूसरे चरण में कार्य किया जाएगा। पहले चरण में पुनर्विकास के लिए परियोजना लागत २१८ करोड़ रुपये तय की गई है। इसके पुनर्विकास के लिए डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल को अपनाया गया है। अंधेरी स्टेशन के कार्यालय का प्लान भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ने तैयार कर लिया है। अंधेरी स्टेशन को २१ हजार ८४३ वर्ग मीटर में बनाया जाना है। इसके पुनर्विकास के मॉडल को सक्षम प्राधिकारी के पास अनुमोदन के लिए भेजा दिया गया है। अंधेरी रेलवे स्टेशन के पहले चरण के विकास के लिए योग्यता के लिए अनुरोध, तब जारी किए जाएंगे, जब वह दोबारा जरूरी होंगे। अंधेरी स्टेशन के मास्टर प्लान के फ्लोर प्लान के लिए अतिरिक्त मंजूरी पहले से ही २१ मई २०२१ को पश्चिमी रेलवे से प्राप्त किया गया है।

अंधेरी स्टेशन का पुनर्विकास होने के बाद स्टेशन का कॉनकार्स पूर्वी तरफ दिया जाएगा। सभी फ्लाईओवर ब्रिज और रेलवे स्टेशन के साथ मेट्रो स्टेशन को एक करेगा। इसके अलावा स्टेशन पर भीड़ को कम करने के लिए प्रवेश, ड्रॉप-ऑफ, पिकअप के लिए बसोंवा मार्ग रोड पर योजना

बनाई गई है। स्टेशन की छत को पूरी तरह से आसमान के साथ-साथ स्वामी नित्यानन्द मार्ग रोड के साथ एक किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी छत बनाने की योजना बनाई गई है, जैसे उपनगरीय स्टेशनों चर्चगेट और सीएसएमटी स्टेशनों में बारिश में पानी और सीधे सूर्य के प्रकाश को मंच में रोकने के लिए है।

स्टेशन शत-प्रशित दिव्यांग-



सुलभ होगा और ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर विकसित किया जाएगा। यह स्मार्ट स्टेशन के तौर पर पुनर्विकसित किया जा रहा है जिसमें आधुनिक निर्माण प्रबंधन प्रणाली के साथ सीसीटीवी सहित अन्य उपकरण लगे होंगे। यहां वाणिज्यिक विकास की योजना भी कॉनकार्स लेवल पर तैयार की गई है जो यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके।

पश्चिमी रेलवे नेटवर्क के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक अंधेरी दो प्रमुख रेलवे लाइनों के लिए सेवा देता है। इसमें हार्बर लाइन जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या पनवेल की ओर जाती है, जबकि पश्चिम रेलवे लाइन को जोड़ने वाले चर्चगेट और दहानू हैं। इसके अलावा वसोंवा- अंधेरी - घाटकोपर मेट्रो लाइन स्टेशन के पूर्व में स्थित है। अंधेरी लंबी दूरी की गाड़ियों के लिए एक प्रमुख स्टेशन है और प्रतिदिन लगभग ४.२ लाख यात्रियों को संभालता है।

भिखारियों को भी काम करना चाहिए, सबकुछ राज्य ही उन्हें नहीं दे सकता

मुंबई- बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि बेघरों और भिखारियों को भी देश के लिए कुछ काम करना चाहिए क्योंकि राज्य ही सबकुछ उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकता। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए बृजेश आर्य की उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को शहर में बेघर व्यक्तियों, भिखारियों और गरीबों को तीन वक्त का भोजन, पीने का पानी, आश्रय और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। बीएमसी ने अदालत



को सूचित किया कि गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मदद से पूरी मुंबई में ऐसे लोगों को भोजन और समाज के इस वर्ग की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है। अदालत ने बीएमसी की इस दलील को मानते हुए कहा भोजन और सामग्री वितरण के संबंध में आगे निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा, "उन्हें (बेघर व्यक्तियों को) भी देश के लिए कोई काम करना चाहिए। हर कोई काम कर रहा है। सबकुछ राज्य द्वारा ही नहीं दिया जा सकता है। आप (याचिकाकर्ता) सिर्फ समाज के इस वर्ग की आबादी बढ़ा रहे हैं।"

राफेल केस में नया मोड़: सौदे की जांच को जज नियुक्त

भारत में अगले साल तक सभी ३६ राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। २०१६ में हुई इस डील को लेकर अब तक कई विवाद उभर चुके हैं। हालांकि, मोदी सरकार अब तक डील में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों से इनकार करती आ रही है। हालांकि, इस बीच फ्रांस में भ्रष्टाचार इस डील को लेकर इक्वायरी शुरू हो गई है। बताया गया है कि इसी एविएशन और भारत सरकार के बीच हुई इस डील में कथित भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की न्यायिक जांच के लिए एक जज की भी नियुक्ति की गई है। फ्रांस के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नल (पत्रिका) के मुताबिक, दोनों देशों की सरकार के बीच १४ जून

२०१६ को जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उस पर एक एक उच्च-स्तरीय संवेदनशील जांच बिठा दी गई है। बता दें कि फ्रांस के ही एक और मीडिया पोर्टल मीडियापार्ट ने शुक्रवार को



खुलासा किया था कि यह आपराधिक जांच एक स्वतंत्र मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाएगी, जो कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद के इस डील में उठाए गए कदमों पर सवालों की जांच करेगा।

गौरतलब है कि जब भारत और फ्रांस के बीच राफेल जेट डील तय हुई थी, तब फ्रांसिस ओलांद ही राष्ट्रपति थे। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उस सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस मामले में फ्रांस की वित्तीय अपराधों से जुड़ी शाखा- फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस (इन्ड) ने कहा है कि वह ३६ राफेल बेचे जाने के मामले में कथित भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की जांच करेगी। कुछ दिन पहले फ्रांसीसी मीडिया प्रकाशन 'मीडियापार्ट' ने देश की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी की जांच का हवाला देते हुए खबर प्रकाशित की थी कि 'दसौ एविएशन' ने एक भारतीय बिचौलिए को दस लाख यूरो की रिश्वत दी थी।

अब नहीं होगा फर्जी वैक्सीनेशन! BMCने जारी की नई गाइडलाइन



मुंबई- मुंबई में कोविड-१९ वैक्सीनेशन में कथित घोटाले की मौजूदा घटनाओं के मद्देनजर बीएमसी ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि हाउसिंग सोसायटी और कार्यालय में निजी टीकाकरण केंद्र कोविन पोर्टल पर पंजीकृत कराने के बाद ही लगाए जा सकते हैं। इस बाबत बीएमसी ने केंद्र सरकार के कोविन पोर्टल पर शहर के पंजीकृत ९५ निजी टीकाकरण केंद्रों की सूची भी जारी की है और इसके साथ ही वार्ड स्तर पर वॉर रूम के नंबर भी जारी किए गए हैं। रजिस्टर्ड सेंटर पर ही वैक्सीनेशन गुरुवार को बीएमसी द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक हाउसिंग सोसायटी और कार्यालय में पंजीकृत निजी कोविड टीकाकरण केंद्र के जरिये ही कोविड टीके लगाए जा सकेंगे।

इसके अलावा कार्यालय और हाउसिंग सोसायटी का प्रबंधन स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करेगा कि सेंटर कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड है। बीएमसी के मुताबिक कार्यालय और हाउसिंग सोसायटी प्रबंधन एक व्यक्ति को 'नोडल अधिकारी' के तौर पर नियुक्त करेंगे, जो निजी टीकाकरण केंद्र और टीकाकरण से

जुड़ी गतिविधियों का समन्वय करेगा। दिशा निर्देश में कहा गया कि नोडल अधिकारी टीकाकरण से जुड़े सभी पहलुओं को देखेगा, जैसे लाभाथि-यों का पंजीकरण, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। उल्लेखनीय है कि बीएमसी ने पिछले महीने कार्यालय और हाउसिंग सोसायटी में टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें

निजी टीकाकरण केंद्रों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन इसकी विस्तृत भूमिका और जिम्मेदारी दिशानिर्देश में नदारद थी। दिशानिर्देश के मुताबिक हाउसिंग सोसायटी संबंधित चिकित्सा अधिकारी और स्थानीय पुलिस थाने को टीकाकरण शिविर के बारे में कम से कम तीन दिन पहले सूचित करेगी।

तीसरी लहर से निपटने के लिए हजार डॉक्टरों को दी ट्रेनिंग
मुंबई में संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बीएमसी पूरी तरह से जुटी हुई है। डॉक्टरों की ट्रेनिंग से लेकर मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बीएमसी ने अब तक ऑनलाइन ट्रेनिंग के पांच सत्र आयोजित किए हैं, जिनमें एक हजार से अधिक डॉक्टरों को तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसमें स्लम इलाकों में प्रैक्टिस करनेवाले जनरल फिजिशियन से लेकर पीडियाट्रिक डॉक्टर तक शामिल हैं।

जलवायु में बदलाव से महाराष्ट्र में कृषि उत्पादकता पर असर पड़ने की संभावना -सर्वे

मुंबई (तुषार चौहान)- इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल कम्यूनिटीज़ (आई.एस.सी.) के एक अध्ययन के अनुसार, महाराष्ट्र को जलवायु में बदलाव से बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राज्य में उगाई जाने वाली चार प्रमुख फसलों - सोयाबीन, कपास, गेहूं और चना के उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है। 'महाराष्ट्र की कृषि पर जलवायु में बदलाव का प्रभाव' शीर्षक वाली रिपोर्ट में राज्य के खानदेश, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के ८ जिलों में इतिहास (साल १९८९-२०१८ को कवर करते हुए) और पूर्वानुमान (२०२१-२०५० को कवर करते हुए) के तहत बारिश और तापमान डेटा के सप्ताह-वार ३० साल के औसत की जांच की गई है।



आई.एस.सी. में जल और कृषि कार्यक्रम के एसोसिएट निदेशक, रोमिंत सेन ने कहा, 'इस रिपोर्ट में पेश किया गया विशेषण, जलवायु मॉडलिंग और अनुमानों (ऐतिहासिक और भविष्य दोनों) का मापन, फसल की फ़ीनोलॉजी (फसल के लिए हर बढ़ते चरण में उत्तम स्थिति) के साथ-साथ समुदाय-आधारित भागीदारी आकलन (जमीन पर किसान सत्यापन) के साथ किया जाता है। ऐसा बहुत बारीक 'साप्ताहिक' पैमाने पर किया जाता है ताकि हर फसल और किसान पर जलवायु में

बदलाव के संभावित असर को अच्छी तरह से समझा जा सके। जलवायु का विशेषण करने से मानसून (खरीफ) और सर्दियों (रबी) के मौसम में फसल की फ़ीनोलॉजी के साथ ही बारिश और तापमान के पैटर्न में मेल न खाने का अनुमान भी लगाया जाता है।'

मानसून के देर से आने और रुक-रुक सूखा पड़ने और बारिश होने से सोयाबीन और कपास के अंकुरण पर असर पड़ा है। खरीफ के मौसम के बीच में ही अधिक बारिश होने से से फंगल रोगों, खरपतवारों और कीटों में वृद्धि होगी। इससे सोयाबीन में फली

के उत्पादन और कपास में बीजकोष बनने पर असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, जल भराव वाली मिट्टी और नमी के हालातों से सड़ांध बढ़ेगी, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों और उर्वरकों में कमी आएगी। खरीफ की अध्ययन की गई फसलों - सोयाबीन और कपास दोनों के लिए फल बनने और पकने की स्थिति के दौरान ज्यादा बारिश का समग्र प्रभाव पैदावार और गुणवत्ता पर पड़ेगा।

आने वाले सालों में गेहूं की खेती के लिए सबसे बड़ी चुनौती अनाज पकने के समय ज्यादा तापमान का रहना होगा। तापमान बढ़ने से अनाज का वजन कम हो जाता है, और अनाज भरने के दौरान तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया जाता

है। चने की खेती में फली भरने के दौरान तापमान में अचानक वृद्धि होगी, जिससे फली कम भरेगी।

इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल कम्यूनिटीज़ के कंट्री डायरेक्टर-इंडिया, विवेक पी. अधिया ने कहा, 'रबी की फसल के मौसम के लिए बहुत कम या लगभग न के बराबर बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जिससे फसल पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर हो गई है। चूंकि भूजल सिंचाई के लिए पानी का प्रमुख स्रोत होता है, इसलिए भूजल जलवाही स्तरों पर दबाव बढ़ेगा। कृषि पर जलवायु में बदलावों के असर को कम करने के लिए जलवायु का बारीक डेटा तैयार करना, कृषि से संबंधित फैसलों पर जानकारी हासिल करना, इनपुट की गुणवत्ता में सुधार करना, खेती के बेहतर अभ्यासों पर ज्ञान बढ़ाना और संसाधन संरक्षण के लिए बेहतर प्रबंधन अभ्यासों को अपनाने की कोशिश करना ज़रूरी है।' ज्यादा तापमान, बारिश, और आर्द्रता के असर की वजह से किसानों के लिए बाहर काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, तेज़ गर्मी और आर्द्रता के बढ़ते मामलों का असर खेती के कार्यों जैसे निराई और कटाई पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र में किसानों के साथ काम करते हुए, आई.एस.सी. खेती के स्थायी अभ्यासों को बढ़ावा देने, जलवायु में बदलाव के संभावित असरों की समझ बनाने और कृषक समुदायों के लिए सहूलियतों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कोरोना महामारी के दौर में हर हालत में रोकी जाएं जनसभाएं



मुंबई- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर आयोजित होने वाली राजनीतिक जनसभा और कार्यक्रम को हर हालत में रोकने का निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में जारी महामारी दौर में ऐसा करना ज़रूरी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि कोविड के बीच प्रदेश में कैसे रैलियां और लोगों के जमावड़े होने दिए जा रहे हैं? पीठ ने पिछले हफ्ते नवी मुंबई में हजारों लोगों की रैली का उल्लेख करते हुए पूछा। वह रैली निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बाल ठाकरे के नाम पर रखे जाने की मांग को लेकर हुई थी। यह रैली तब हुई जब राज्य सरकार ने कोविड-१९ को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा रखी है। पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष

कुंभकोनी की ओर मुखातिब होकर कहा कि महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी मशीनरी के जरिये कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर होने वाली जनसभाओं और अन्य जमावड़ों को रोके। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो यह कार्य कोर्ट करेगी। हम इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने दे सकते। अगर हम महामारी को फैलने से रोकने के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करा सकते तो कोर्ट बंद कर देनी चाहिए।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बीएमसी ने बच्चों पर सीरो सर्वे करवाया है। बीएमसी के अनुसार, इस सर्वे से मालूम चला कि मुंबई में एक से १८ वर्ष के आयु वर्ग के ५१.१८ प्रतिशत बच्चों में कोरोना संक्रमण से मुकाबला करने वाली एंटीबाडी मौजूद है। बृहमुंबई नगर निगम २, १७६ सैंपल की जांच की गई।